शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 19 – 26 अगस्त 2024 मूल्य पांच रूपये

एचआरटीसी की खरीद से नादौन में लैण्ड सीलिंग पर उठे सवाल

- क्या सीलिंग एक्ट के बाद भी सीलिंग से अधिक जमीन खरीदी जा सकती है ?
- 28 जनवरी 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना में सरकार खामोश क्यों ?
- 2011 के पावर ऑफ अटार्नी पर 2015 में अमल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में सरकार ई-बसों के लिए एक बस स्टैंड का निर्माण करने जा रही है। इस बस स्टैंड के लिए कलूर के मौलाघाट में एचआरटीसी ने जमीन ली है। जिन लोगों से यह जमीन 2023 में खरीदी गई है उन्होंने स्वयं 2015 में यह जमीन राजा नादौन महेश्वर चन्द से करीब 2,40,000 में खरीदी थी। राजा महेश्वर चन्द से हुई यह खरीद ही अपने में एक अवैध खरीद होने 2की आशंका है। क्योंकि 1974 में पारित और 1971 से लागू हुए लैण्ड सीलिंग एक्ट के मुताबिक महेश्वर चन्द के पास बची ही केवल 30 स्टैंर्ड एकड़ (316 कनाल 10 मरले) जमीन थी। महेश्वर चन्द की शेष जमीन लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार में विहित हो गयी थी। इसलिए लैण्ड सीलिंग एक्ट के लागू होने के बाद महेश्वर चन्द द्वारा बेची गयी सैकड़ो कनाल जमीन अपने में एक स्कैन का रूप ले लेती है।

स्मरणीय है कि राजा नादौन को 1897 में अंग्रेज शासन के दौरान 1,59,986 कनाल 6 मरले जमीन बतौर जागीर मिली थी। यह जमीन नादौन रियासत के 329 गांवों मैं फैली थी और इस पर स्थानीय लोगों के बर्तनदारी अधिकार सुरक्षित रखे गये थे। आज भी राजस्व रिकॉर्ड में पर्चा जमाबंदी में 'ताबे हकूक बर्तनदारान' दर्ज है। जब हिमाचल में लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू हुआ तो उसमें अधिकतम भू-सीमा 30 एकड़ कर दी गयी। इससे अधिक की जमीन का भू स्वामी को मुआवजा देकर ऐसी जमीने सरकार के अधिकार क्षेत्र में चली गयी। राजा नादौन की भी सारी जमीन सरकार में चली गयी थी। लैण्ड सीलिंग से 515 कनाल 14 मरले जमीन तहसील देहरा के नौरी गांव में चाय बागान के नाम पर बाहर रही। इसी तरह टीका नागरा में 32 कनाल 12 मरले और टीका कलूर में 1224 कनाल 4 मरले भू-दान यज्ञ बोर्ड के नाम होने से सीलिंग से बाहर रही। लेकिन वर्तमान में नौरी में कोई चाय बागान नहीं है और न ही कलूर में ऐसी कोई जमीन भू-दान बोर्ड के नाम पर होने की स्थानीय लोगों को कोई जानकारी है जबकि यह सब वित्तायुक्त के 31-7-84 के फैसले में दर्ज है। वित्तायुक्त के फैसले के अनुसार राजा नादौन की सीलिंग में आयी एक लाख कनाल से अधिक की विलेज कामन लैण्ड घोषित है ।

विलेज कामन लैण्ड की कोई खरीद बेच नहीं हो सकती यह सर्वोच्च न्यायालय के 28 जनवरी 2011 के फैसले से स्पष्ट है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने विलेज कामन लैण्ड को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए समय-समय पर इस सन्दर्भ में शीर्ष अदालत में रिपोर्ट दायर करने को कहा है। हिमाचल में सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की अनुपालना में क्या कदम उठाए गए इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इस फैसले के बाद राजा नादौन महेश्वर चन्द ने दिसंबर 2011 में अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी एक हरभजन सिंह के नाम बना दी। 2015 में इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से एचआरटीसी द्वारा खरीदी गई जमीन बेची थी। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाये जाने को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह है। सीलिंग एक्ट के आने के बाद जब महेश्वर चन्द के पास बची ही 316 कनाल थी तो उसने सैकड़ो बीघे जमीन बेच कैसे दी? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना में क्या कदम उठाए गए? बल्कि जब सरकार 2023 में लैण्ड सीलिंग एक्ट को लेकर संशोधन लायी तब भी सरकार ने यह जानकारी नहीं जुटाई कि आज भी प्रदेश में कितने लोगों के पास लैण्ड सीलिंग सीमा से अधिक जमीन है और क्यों है। क्योंकि नादौन में ही ऐसे मामले सामने आये हैं जिन्होंने राजा नादौन से सीलिंग से अधिक जमीन खरीद रखी है। यह सारे सवाल एचआरटीसी द्वारा 70 कनाल पौने सात करोड़ में खरीदने के बाद उठे हैं क्योंकि सीलिंग के बाद शायद इस जमीन की मालिक ही सरकार थी ।

एकीकृत पैन्शन योजना कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी:जयराम

शिमला/शैल। जयराम ठाकुर ने कहा की जब चुनाव चल रहे थे तब ओपीएस को लेकर हमने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था की भाजपा देश भर में कर्मचारियों को लेकर गंभीर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा गंभीरता से आगे बड़ी और देश भर में एकीकृत पैन्शन योजना लाने का काम किया जिससे पूरे देश के कर्मचारी खुश है, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिससे सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा की एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी कई खास बातें है जैसे पैन्शन की सनिश्चित राशि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पैन्शन के रूप में मिलेगा। 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए अनुपातिक राशि पैन्शन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पैन्शन सुनिश्चित की जाएगी, 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पैन्शन राशि मिलेगी और अनेकों फायदे कर्मचारियों को होंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा की सीएम सुक्खू को कर्मचारियों के मुद्दे पर अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए। हिमाचल में कर्मचारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, के बीच में जो वातावरण चल रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कर्मचारी सड़को पर क्यों है? कर्मचारी परेशान क्यों है? पूरे प्रदेश में प्रमोशन, डीए, एरियर सब लंबित क्यों है?

उन्होंने कहा की सीएम साहब भाषण बहुत हुये अब समाधान का समय है। प्रदेश में कर्मचारियों को विरोध नहीं समाधान चाहिए। भाजपा जब सत्ता में थी तो कभी वेतन नहीं रुका, डीए समय पर दिया गया और सभी मामलों को गंभीरता से सुना गया, इस बार तो कर्मचारियों की तो सुनवाई ही नहीं है।

उन्होंने कहा की भाजपा आगमी विधानसभा सत्र में कांग्रेस को महंगाई, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, के अनेकों विषयों पर घेरेंगे। कांग्रेस राज में विकास ठप और कुप्रबंधन अप हो चुका है।

राज्यपाल ने सीपीआरआई शिमला के 76वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की

प्रदेश में आलू आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर दिया बल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत किसानों को आय

के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने राज्य में आलू आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) शिमला के 76वें स्थापना दिवस पर मुख्यातिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने संस्थान को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि लोगों को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए फसलों का विविधिकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा क आलू देश की प्रमुख फसल है, जिसका कुल सब्जी उत्पादन में 28 प्रतिशत योगदान है। उन्होंने कहा कि विश्व में चीन के बाद भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है। वैश्विक आलू उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत उत्पादन भारत में किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने आलू के निर्यात मूल्य में 20 अरब रुपये से अधिक की रिकॉड बढ़ोतरी दर्ज की थी।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 14000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की जाती है, जिसमें लगभग दो लाख टन आलू का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल में उच्च गुणवत्ता वाले आलू उगाए जाते हैं, जिससे किसानों को अच्छी आय होती है। उन्होंने संस्थान को कुफरी हिमालिनी, कुफरी गिरधारी और कुफरी करण जैसी तुषार ब्लाइट प्रतिरोधी आलू की किस्में विकसित करने के लिए बधाई दी।

शुक्ल ने कहा कि संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्य और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के कारण भारत विश्व में आलू के प्रमुख उत्पादक के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले सात दशकों में आलू उत्पादन तथा आलू उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

उन्होंने संस्थान को आलू की 70 से अधिक किस्में विकसित करने और वायरसमुक्त बीज आलू के उत्पादन के लिए एरोपोनिक तकनीक विकसित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने प्रजातियों और तकनीकों के भौतिक संरक्षण के लिए संस्थान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्थान को 25 से अधिक पेटेंट करने के लिए भी बधाई दी। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में राज्य में आलू की खेती के प्रति किसानों की घटती रूचि पर चिंता व्यक्त की और वैज्ञानिकों से अनुसंधान के माध्यम से इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का पता लगाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने आईसीएआर-सीपीआरआई शिमला के कर्मियों को इस क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया। उन्होंने संस्थान के कर्मचारियों को उत्तर भारत खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार और किसानों को कृषि उपकरण भी वितरित किए।

नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आलू उत्पादन में वृद्धि के लिए तकनीक के उपयोग पर बल दिया।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इससे पूर्व, आईसीएआर- केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया और संस्थान की उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया।

सामाजिक विज्ञान प्रभाग के प्रमुख डॉ. आलोक कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सीपीआरआई शिमला के वैज्ञानिक प्रगतिशील किसान और ऑकलैंड हाउस स्कूल के विद्यार्थी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।

राज्यपाल ने जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां और ऊर्जा का संचार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को सभी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। वर्तमान में भगवत गीता की शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हैं। हम सभी को इन पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा।

राज्यपाल ने कैथलीघाट में शुंगल सुरंग का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला के कैथलीघाट के नजदीक शिमला बाइपास सुरंग-1 पोर्टल-2 शुंगल का दौरा किया। उन्होंने प्रगति कार्य का निरीक्षण किया और परियोजना के बारे में विस्तार से

जानकारी ली।

28.5 किमी लंबे फोरलेन शिमला बाइपास पैकेज-1 व 2 पर 10.6 किमी लंबी 10 सुरंगों का निर्माण किया जाना है और इसमें 27 बड़े पुल और वायाडक्ट भी होंगे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने बाईपास की टनल 1 की बाई टयूब का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से कैथलीघाट से ढली की दूरी लगभग 15 किलोमीटर कम हो जाएगी तथा यात्रा में लगभग एक घंटे का समय बचेगा। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के निर्माण से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने लगभग 5,000 पेड़ों को कटने से बचाया है तथा मिटी के कटाव को भी रोका है।

उन्होंने कहा कि यह सुरंग पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित तथा सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इससे वाहनों के ईंधन की बचत होगी, जिससे वायु प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। वहीं, 10 सुरंगों के निर्माण से लगभग 22,500 पेड़ों को कटने से बचाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकरी अब्दुल बासित ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि दोनों चरणों में सुरंग की कुल लंबाई 1,410 मीटर होगी और जनवरी 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य पर 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उन्होंने अवगत करवाया कि शिमला बाइपास फोरलेन परियोजना की कैथलीघाट से ढली तक कुल लागत 4,800 करोड़ रुपये है और इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और एनएचएआई के अन्य अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे।

हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के प्रयासों से राज्य के कारीगर हो रहे लाभान्वित:उद्योग मंत्री

निगम ने तीन माह में 412.99 लाख रुपये के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की बिक्री की

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के निदेशक मंडल की 192वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर 23.38 करोड़ रुपये की लागत की केन्द्रीय

प्रायोजित योजना 'व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना' सीएचसीडीएस के कार्यान्वयन की समीक्षा की। आगामी तीन वर्षों तक चलने वाली इस योजना का उद्देश्य राज्य में हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 में निगम की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान प्रदेश के 420 कारीगरों को विभिन्न पहलों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक 107 डिज़ाइन और तकनीकी विकास कार्यशालाएं तथा छह उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिससे प्रदेशभर के 2500 कारीगरों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की राज्य के कारीगरों द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के भीतर विषयगत प्रदर्शनियों के आयोजन की योजना है। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत दो नये इम्पोरिया खोले जाएंगे और छह मौजूदा इम्पोरिया का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

हर्षवर्धन चौहान ने राज्य के कारीगरों और बुनकरों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निगम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य के कारीगरों के लिए निगम द्वारा शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निगम को राज्य के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।प्रबन्ध निदेशक गन्धर्व राठौर ने निगम की प्रमुख गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया और कहा कि निगम द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में 40.92 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया, जबकि 1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक निगम ने 412.99 लाख रुपये के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की बिक्री की। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष शिमला और धर्मशाला में दो 'ताना-बाना' हथकरघा एक्सपो आयोजित किए जा रहे हैं। जहां 25 बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए निःशुल्क स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रधान सचिव उद्योग आरडी नज़ीम और निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति भी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक संदीप भारद्वाज के नेतृत्व में भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। उन्होंने एचआरटीसी की बसों में रियायती यात्रा सुविधा बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और वर्तमान प्रदेश सरकार पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी 210 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की है, जिसमें पांच गुणा बढ़ोतरी की गई है जोकि राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है।

उन्होंने पुलिस फोर्स की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रथम पंक्ति के रक्षक हैं जिनकी कानून व्यवस्था को कायम रखने में अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिर और शांतिपूर्ण समाज के लिए पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ न्याय के लिए निष्ठा से कार्य करते हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों के अलावा वे प्राकृतिक आपदा और संकट के समय में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जहां वे लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस यातायात प्रबंधन, यातायात कानूनों को लागू करने और दुर्घटना होने पर तुरन्त मुस्तैदी से कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं और यह सभी तरह की सार्वजनिक सुरक्षा में योगदान देते हैं।

'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' लागू करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को

अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठयंक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

बैठक में 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023' के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किश्त के वितरण के उपरान्त तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में छः माह की छूट को स्वीकृति प्रदान की। इससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी।

मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों जेल वॉर्डन से गैर-राजपत्रित रैंक के एक्जिक्यूटिव स्टाफ और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के डाडासीबा में एक नया उप मंडल पुलिस कार्यालय व आलमपुर में पुलिस पोस्ट स्थापित करने तथा संसारपुर टैरेस व मोइन पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।

बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में जल शक्ति विभाग का नया सर्कल खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में जल शक्ति विभाग का एक नया उप-मण्डल और अनुभाग स्थापित कर आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे। जिला ऊना के हरोली क्षेत्र के खड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का एक नया उप-मण्डल खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने शिमला के कोटखाई के गुम्मा क्षेत्र के उबादेश में अग्निशमन चौकी खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के ईएनटी व मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद भरने की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त रोगियों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए तीन टेस्ला एमआरआई मशीनें खरीदने की अनुमति प्रदान की। अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा व इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने विद्युत क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी स्लैब को 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से क्रमशः 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के समर्पण और ईमानदार प्रयासों के फलस्वरूप चंद्रयान-3 मिशन सफल हो पाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिला के शोघी में 7 अक्तूबर, 2023 को उन्होंने विज्ञान अध्ययन एवं सृजनात्मकता केंद्र का उद्घाटन किया था। इस केंद्र में पहला तारामंडल शीघ्र ही क्रियाशील हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस केंद्र में रखे गए विभिन्न मंडलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से बच्चों के लिए विज्ञान के अध्ययन को और अधिक रोचक और नवीन बनाया गया है। उन्होंने इस केंद्र की स्थापना में हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी।

उद्योग मंत्री ने एचपीजीआईसी की बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 231वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, बोर्ड ने राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के सात प्रतिशत लाभांश 50,06,978 रुपये के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की। यह लाभांश राज्य सरकार के पांच प्रतिशत के मानक से दो प्रतिशत अधिक है।

उद्योग मंत्री ने अप्रैल से मई 2024 के दौरान निगम के बेहतर प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि निगम ने लगभग 2.85 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों को मंजूरी देने के अलावा, बोर्ड ने इस अवधि के लिए निगम के 1.33 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट को भी मंजूरी दी, जिससे निगम को लगभग 10 करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद है।

निगम के प्रबंध निदेशक अरिंदम चौधरी ने बोर्ड को निगम द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया।

बैठक में प्रधान सचिव उद्योग आर. डी. नज़ीम और निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति भी उपस्थित थे।

आपराधिक मामलों को सुलझाने में फॉरेंसिक विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक साइंस विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपराध अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया की समयावधि को कम

करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों को सुलझाने एवं अपराधियों को पकड़ने में फॉरेंसिक विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा प्रदेश सरकार विभाग के आधुनिकीकरण के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने न्यायालयों में अपराधियों को सजा दिलवाने की दर में सुधार लाने के लिए आपराधिक रिपोर्टों की गुणवत्ता को बेहतर करने पर बल दिया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अपराधी को कानून के तहत सजा दिलवाने के लिए आपराधिक मामलों के प्रभावी प्रबन्धन की आवश्यकता है, जिसके लिए अपराध स्थल की जांच कर सही तरीके से नमूने एकत्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपराध स्थल से जो नमूने एकत्रित किए जाते हैं, उनकी विश्वसनीयता एवं सटीकता बनाए रखने के लिए विभाग को बार कोडिंग प्रणाली विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों की सही तरीके से जांच के लिए प्रदेश सरकार चार फॉरेंसिक वाहन प्रदान करेगी। विभाग में विभिन्न रिक्त पदों को भरा जाएगा तथा अधोसंरचना को भी मौजूदा समय के अनुसार विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की बेहतर कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक बिहेवियरल एनलेसिज यूनिट, फूड फोरेंसिक यूनिट सहित अन्य नए यूनिट स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने फोरेंसिक विभाग में कर्मचारियों के युक्तिकरण पर बल दिया और कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर एवं लाहौल-स्पीति जिलों में जिला फोरेंसिक यूनिट स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक किया जाएगा, जिसके लिए नवीन तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, महाधिवक्ता अनूप रतन, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, फॉरेंसिक साइंस की निदेशक डॉ. मिनाक्षी महाजन और बोर्ड के अन्य सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।

सरकार पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयासरत:बाली

शिमला/शैल। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली और पर्यटन एवं नागरिक उड्यन विभाग की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर ने इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को विकसित करने के लिए वैकल्पिक स्थलों की खोज करने और पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा, सम्पर्क एवं सुविधाएं बढ़ाने पर बल दिया गया। सम्मेलन में निजी क्षेत्रों से निवेश आकर्षित करने के लिए रणनीति साझा करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में विभिन्न पहल की गई हैं और निवेशकों को अनेक प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। केन्द्रीय राज्य पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी, पर्यटन सचिव, पर्यटन महासचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

दुनिया मज़ाक करे या तिरस्कार , उसकी परवाह किये बिना मनुष्य को अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिये।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कर्मचारी आन्दोलन को हल्के से लेना घातक होगा

आन्दोलन ने सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाये हैं

सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी दी थी। प्रदेश की जनता ने इस चेतावनी पर कोई सवाल नहीं उठाये। सरकार ने इस चेतावनी का कवर लेकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये जो कदम उठाये उन कदमों के तहत मध्यम वर्ग को मिल रही सुविधाओं पर कटौती की जाने लगी। जो आज सस्ते राशन के दाम बढ़ाने तक पहुंच गयी है। इस कटौती के साथ ही प्रदेश पर कर्ज भार भी बढ़ने लगा। लेकिन इन सारे कदमों के साथ सरकार अपने खर्चो पर लगाम नहीं लगा पायी। सरकार के बड़े अधिकारियों के खिलाफ बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उल्टा जब मीडिया ने इन मामलों को उठाया तो मीडिया को ही डराने धमकाने का चलन शुरू हो गया। भ्रष्टाचार की जो शिकायतें मुख्यमंत्री के पास भी पहुंची उन पर भी कोई कारवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर हालात यहां तक पहुंच गये की सरकार पर मित्रों की सरकार होने का तगमा लग गया। यह स्वभाविक है कि जब परिवार संकट में होता है तो सबसे पहले परिवार का मुखिया अपने खर्चो में कटौती करता है तब परिवार उसकी बात पर विश्वास करता है। लेकिन सुक्खू सरकार इस स्थापित नियम पर न चलकर कर्ज लेकर घी पीने के रास्ते पर चल पड़ी।

सरकार और कर्मचारी एक दूसरे का पूरक होते हैं। फिर आज तो कर्मचारियों का हर वर्ग संगठित है। कर्मचारियों में भी सचिवालय के कर्मचारी तो पूरे तंत्र का मूल होते हैं। क्योंकि सरकार का हर फैसला सचिवालय में ही शक्ल लेता है। सचिवालय का कर्मचारी रूल्स ऑफ बिजनेस का जानकार होता है। इस कर्मचारी को सरकार की वित्तीय स्थिति और फिजूल खर्ची दोनों की एक साथ जानकारी रहती है। जब सचिवालय के कार्यरत कर्मचारी यह देखता है कि अफसरशाही और राजनेताओं के खर्चो में तो कोई कटौती नहीं हो रही है बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गये हैं और उसके जायज देय हकों की अदायगी करने के लिये कठिन वित्तीय स्थिति का तर्क दिया जा रहा है। तब वह सारे हालात पर अलग से सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज सचिवालय कर्मचारी संघ सरकार की कथनी और करनी के अन्तर देखकर अपनी मांगों के लिये आवाज उठाने पर विवश हुआ है। सचिवालय के कर्मचारियों के पास हर मंत्री और अधिकारी की तथ्यात्मक जानकारी रहती है। इसी कर्मचारी ने सरकार की फजूल खर्ची का आंकड़ों सहित खुलासा आम आदमी के सामने रखा है। इसी कर्मचारी के माध्यम से यह बाहर आया है कि आपदा राहत का 114 करोड़ रूपया लैप्स हो गया है। आपदा राहत के नाम पर प्रदेश सरकार केंद्र पर किस तरह हमलावर थी यह पूरा प्रदेश जानता है। यदि 114 करोड़ लैप्स होने का खुलासा सही है तो इससे सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

मंत्रियों के कार्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का खुलासा इसी सचिवालय कर्मचारियों ने किया है। कमरे के फोटो तक बाहर आये हैं। जब मंत्रियों के कार्यालय पर खर्च हो रहा है तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी 19 करोड़ खर्च करने का खुलासा इसी सचिवालय कर्मचारी संघ ने सामने रखा है। महंगी गाड़ियों और दूसरे खर्चो पर पूरी बेबाकी से इन कर्मचारियों ने खुलासा सामने रखा है। जो कुछ सरकार की फजूल खर्ची को लेकर कहा गया है वह पूरे प्रदेश में हर आदमी तक पहुंच गया है। सरकार की ओर से फिजूल खर्ची के आरोपों पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारी आंदोलन की शुरुआत सचिवालय कर्मचारी संघ से हुई है। लेकिन सरकार ने वार्ता के लिये सचिवालय कर्मचारियों को न बुलाकर दूसरे कर्मचारी नेताओं को बुलाया है। क्या सरकार इस तरह कर्मचारियों को विभाजित कर पायेगी इसका पता तो आने वाले दिनों में लगेगा। सचिवालय कर्मचारी संघ विधानसभा सत्र के बाद किस तरह की रणनीति अपनाते हैं यह भी आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जायेगा। लेकिन कर्मचारियों ने सरकार की फिजूल खर्ची पर आंकड़ों सहित जो आरोप लगाये हैं वह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गये हैं। यदि सरकार ने अपने खर्चो पर क्रियात्मक रूप से कटौती न की तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के लिए घृणित कृत्यों की निंदा और युवाओं में राष्ट्रीय सोच डोलने की जरूरत

गौतम चौधरी

विगत 9 जून, 2024 को जम्मू – कश्मीर के रियासी जिले में हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले की निंदा जरूरी है। लेकिन केवल निंदा से काम नहीं होगा। इसके लिए देश के सभी सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा। साथ ही इस प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ देश में एक प्रकार की सकारात्मक और समावेशी शक्ति विकसित करनी होगा। इस क्रूर हमले में, शिव खोरी मंदिर से कटरा तक 53 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें नौ लोगों की दुखद मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। भारी गोलीबारी की चपेट में आने के बाद पोनी क्षेत्र के टेरयाथ गांव के पास बस सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई। इस प्रकार की घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हों वे न तो किसी कौम का हित कर सकते हैं और न ही किसी धर्म या संप्रदाय का। इस घटना की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने निंदा की है, जम्मू – कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिज्ञा की है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस विनाशकारी हमले के आलोक में, पूरे समुदाय के लिए ऐसी हिंसा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना महत्वपूर्ण है। यह हमला सिर्फ पीड़ितों और उनके परिवारों पर नहीं किया गया है, बल्कि हमारे समावेशी समाज के शांति और सद्भाव पर प्रहार किया गया है। सभी धर्मो के लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे आतंक के इस कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करें और शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें और धर्म के नाम पर की जाने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा को खारिज करें।

आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति के संदेश को बढ़ावा देने में सामुदायिक नेताओं, संगठनों और परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवाओं को उनके धर्म की सच्ची शिक्षाओं के बारे में शिक्षित करना, जो शांति, करुणा और सह – अस्तित्व की वकालत करती है, सर्वोपरि है। युवाओं को आतंकवादी समूहों की चालाकीपूर्ण रणनीति के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, जो व्यक्तियों को भर्ती करने और कट्टरपंथी बनाने के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं।

युवा पीढ़ी को राष्ट्र व समाज विरोधी तत्वों, नफरत फैलाने वालों का शिकार बनने से रोकने के लिए कई उपाय लागू किए जाने चाहिए। धार्मिक और सामुदायिक नेताओं द्वारा आयोजित सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम युवाओं को आतंकवाद के खतरों और राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ मजबूत संबंध बनाने से समुदायों के भीतर कट्टरपंथ के प्रयासों को पहचानने और रोकने में मदद मिल सकती है। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करना चाहिए जो आलोचनात्मक सोच, सहिष्णुता और विविधता के मूल्य को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवादी समूहों के दुष्प्रचार का प्रतिकार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सकारात्मक संदेश और प्रति – कथाएँ फैलाई जानी चाहिए।

इस दुखद घटना के जवाब में, मुस्लिम समुदाय के लिए आतंक के ऐसे कृत्यों के खिलाफ कड़ी निंदा करना महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसकी निंदा की भी है। इसके अतिरिक्त, मुस्लिम युवाओं को शिक्षित और संवेदनशील बनाने और उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से इनकार करने और इसके बजाय इन खतरों के खिलाफ एकजुट होने के लिए मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। शांति के संदेश को बढ़ावा देकर और हिंसा को अस्वीकार करके, समुदाय एक सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण भारत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ मिलकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नफरत और विभाजन की ताकतों को हराया जाए, जिससे हमारा देश विविधता और सद्भाव के प्रतीक के रूप में विकसित होता रहे।

सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत चंबा ज़िला में 86 करोड़ 55 लाख व्यय

53 हजार 616 पात्र लाभार्थियों को मिला विभिन्न योजनाओं का लाभ

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही । राज्य सरकार के व्यवस्था परिवर्तन संकल्प के ज़िला चंबा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं ।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

वर्तमान में राज्य सरकार के व्यवस्था परिवर्तन संकल्प के ज़िला चंबा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों से जुड़कर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोग आज सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं ।

चूंकि चंबा ज़िला की भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में किसी भी योजना या अभियान को सफल बनाने के लिए यहां सामान्य से कहीं अधिक प्रयास करने पड़ते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ज़िला में समाज के पिछड़े वर्गो, असहायों, निराश्रितों को सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

ज़िला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2023 – 24 के दौरान चंबा ज़िला में 86 करोड़ 55 लाख की धनराशि व्यय कर 53 हजार 616 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाभान्वित किया गया ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं वृद्धजनों, विधवाओं, अक्षम व्यक्तियों के सम्मानजनक जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ज़िले में 52 हजार 885 पेंशन धारकों को लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग ने गत वर्ष 84 करोड़ 32 लाख की धनराशि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रदान की है ।

हिमाचल प्रदेश में निराश्रित बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रदेश सरकार की नई पहल 'मुख्यमंत्री सुखआश्रय योजना' ज़िले के उन 23 बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनकी ठहरी उम्मीदों ने अब सुनहरे भविष्य की तरफ उड़ान भरना शुरू कर दिया है।

इसी तरह 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' आरंभ कर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है । ज़िला में इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1245 आवेदन कर्ता महिलाओं को 56 लाख की धन राशि से तीन माह की सम्मान निधि प्रदान की जा चुकी है ।

विभाग द्वारा गत वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 83 पात्र परिवारों को को 1 करोड़ 25 लाख की धनराशि से गृह अनुदान योजना से लाभान्वित किया गया।

विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन कर प्रदेश सरकार जन कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित बना रही है ।

केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के निपटान के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए

शिमला। केंद्र सरकार ने शिकायत निवारण को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप लोक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लोक शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए दिशा-निर्देश नागरिकों को सशक्त बनाने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, लोक शिकायतों के निवारण को लेकर अधिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं।

लोक शिकायतों के निपटान हेतु व्यापक दिशानिर्देशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

1. सीपीजीआरएएमएस के साथ एक एकीकृत उपयोगकर्ता-अनुकूल शिकायत दर्ज करने वाला प्लेटफॉर्म WWW.pgportal.gov.in एक कॉमन ओपन प्लेटफॉर्म है, जो एकल खिड़की अनुभव के रूप में काम करेगा और जिस पर नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायतों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो शिकायतों का शीघ्र, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान करेंगे। शिकायतों का बोझ अधिक होने वाले मंत्रालयों/विभागों में समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

3. नोडल अधिकारी की भूमिका प्रभावी वर्गीकरण, लंबित मामलों की निगरानी, प्रक्रिया और नीतिगत सुधारों के लिए फीडबैक की जांच, मूल कारण विश्लेषण, मासिक डेटा सेट का संकलन और मंत्रालय/विभाग के शिकायत निवारण अधिकारियों की पर्यवेक्षी निगरानी करना है।

4. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले पर्याप्त संसाधनों के साथ समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।

5. प्रभावी शिकायत निवारण की समयसीमा घटाकर 21 दिन कर दी गई है। जिन मामलों में शिकायत निवारण में अधिक समय लगने की संभावना है, वहां नागरिकों को अंतरिम जवाब दिया जाएगा।

6. मंत्रालयों/विभागों में अपीलीय अधिकारियों और उप-नोडल अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति के साथ एक उन्नयन प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है।

7. शिकायतों का निवारण संपूर्ण सरकार वाले दृष्टिकोण से किया जाएगा तथा शिकायत निवारण अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सीपीजीआरएएमएस पर दर्ज की जाएगी।

8. निपटारा की गई शिकायतों के बारे में नागरिकों को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से फीडबैक भेजी जाएगी। प्रत्येक निपटाई गई शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर के माध्यम से फीडबैक एकत्र की जाएगी और यदि नागरिक संतुष्ट नहीं है तो वह अगले वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है।

9. सरकार एआई संचालित विश्लेषणात्मक उपकरणों- ट्री डैशबोर्ड और इंटेलिजेंट ग्रीवन्स मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का उपयोग करके नागरिकों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण करेगी।

10. मासिक आधार पर मंत्रालयों/विभागों की रैंकिंग के लिए शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक जारी किया जाएगा।

11. सीपीजीआरएएमएस पर शिकायत अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सेवोत्तम योजना के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 36 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

12. मंत्रालयों/विभागों को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में समय-समय पर शिकायत निवारण की समीक्षा करने तथा सभी हितधारकों के बीच शिकायत निवारण प्रणालियों के बारे में पर्याप्त संचार और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2024 नीति दिशानिर्देश प्रभावी शिकायत निवारण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और अपनाई गई 10-चरणीय सुधार प्रक्रिया के साथ किए गए प्रौद्योगिकी सुधारों को दर्शाते हैं। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल ने 2022-2024 की अवधि में लगभग 60 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया है और मंत्रालयों/विभागों एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1.01 लाख शिकायत निवारण अधिकारियों को जोड़ा गया है। 2022 नीति दिशानिर्देशों के तहत शिकायत निवारण की समयसीमा 30 दिन थी, जिसे घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने उत्पादन का पहला बड़ा कीर्तिमान प्राप्त किया

शिमला। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) बहुत गर्व के साथ अपनी उत्पादन क्षमताओं की एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा करता है। इस अत्याधुनिक संयंत्र ने सफलतापूर्वक 1 मिलियन टन हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) का उत्पादन किया

है, जो एचआर कॉइल उत्पादन शुरू होने की पहली वर्षगांठ से चार दिन पहले इस मील का पत्थर प्राप्त कर लिया है। यह उपलब्धि एनएसएल की स्थिति को उद्योग में सबसे तेज और सबसे कुशल संयंत्रों में से एक के रूप में रेखांकित करती है, जो इसकी उल्लेखनीय भावना, प्रदर्शन और अत्याधुनिक तकनीक की विशेषता है।

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि 2024 में एनएसएल की पहले की सफलताओं पर आधारित है। 21 जुलाई, 2024 को, कंपनी ने अपने ब्लास्ट फर्नेस से 1. 5 एमएनटी हॉट मेटल का उत्पादन प्राप्त किया, और 11 अगस्त, 2024 को, इसने स्टील मेकिंग शॉप से 1 एमएनटी लिक्विड स्टील का उत्पादन किया। उत्पादन शुरू होने से एक साल से भी कम समय में दोनों मील के पत्थर को प्राप्त किए औरं, उद्योग में प्रदर्शन के लिए नए मानक स्थापित किए।

ये उपलब्धियां एनएसएल की परिचालन उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। कंपनी दक्षता, स्थिरता और तकनीकी उन्नति पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करते हुए इस्पात विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी बनने की आकांक्षा से सीमाओं को आगे बढ़ा रही है।

यह अत्याधुनिक 3 एमटीपीए स्टील प्लांट रुपये के निवेश से स्थापित किया गया है। 22,900 करोड़ के घर में भारत की सबसे चौड़ी हॉट स्ट्रिप मिल्स में से एक है, जो 900 मिमी से 1650 मिमी चौड़ाई के एचआर कॉइल को 1 मिमी से 16 मिमी मोटाई में रोल करने में सक्षम है।

अमिताभ मुखर्जी, सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार), एनएमडीसी और एनएसएल ने इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए अविश्वसनीय रूप से गर्व हो रहा है कि एनएसएल ने अपनी उत्पादन यात्रा में इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया है। निर्धारित समय से पहले 1 एमएनटी हॉट रोल्ड कॉइल (एचसीआर) प्राप्त करना हमारी पूरी समर्पित टीम के समर्पण, विशेषज्ञता और कड़ी मेहनत का एक उदाहरण है। इस उपलब्धि ने न केवल पीएसयू क्षेत्र के भीतर एक नया मानक स्थापित किया, बल्कि उद्योग के बेंचमार्क के खिलाफ भी मजबूती से खड़ा हुआ। हम इस गति को बनाए रखने और गुणवत्ता और दक्षता के साथ नेतृत्व करना जारी रखने पर केंद्रित हैं।

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के तहत एक गतिशील सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने और विनिर्माण प्रौद्योगिकी में अग्रणी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। उत्कृष्टता, स्थिरता और नवाचार पर ध्यान देने के साथ, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड उल्लेखनीय गति और प्रदर्शन के माध्यम से खुद को अलग करता है, कंपनी उन्नति लाने और नए उद्योग मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वामित्व योजना से लोगों को मिला जमीन का मालिकाना हक

ऋण लेने के लिए हुए पात्र, जमीन में कर सकेंगे निवेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी कर एक परिवर्तनकारी शुरूआत की है। यह महत्वाकांक्षी योजना आबादी देह क्षेत्रों आबादी वाले क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि यह योजना प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलेगी जिससे हजारों परिवारों के लिए आर्थिक तरक्की के अवसर बढ़ेंगे।

राजस्व विभाग की अगुवाई में शुरू की गई इस योजना के प्रथम चरण में 190 गांवों के 4,230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई है। अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गांवों में से 13,599 आबादी देह गांवों में से ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला हमीरपुर सहित कुल 6314 गांवों के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे और दूसरे स्तर के 774 गांवों के 1482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही जिला हमीरपुर में 355 आबादी देह गांवों के अंतिम स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

हमीरपुर देश का पहला जिला बना है, जहां आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। लाल डोरा में रहने वाले परिवारों को भूमि का अधिकार मिलने से उनकी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। राज्य सरकार पहले ही दिन से लोगों की सुविधा के लिए अनेक कार्य कर रही है।

संपत्ति कार्ड न केवल कानूनी दस्तावेज हैं, बल्कि लाल-डोरा/लाल-लकीर क्षेत्रों के निवासियों द्वारा लंबे समय पेश आ रही मुश्किलों और मुद्दों का समाधान है। संपत्ति कार्ड आधिकारिक भूमि अभिलेखों तक लोगों की पहुंच को सरल बनाएंगे, जिससे राजस्व कार्यालयों में बार-बार आने जाने की जरूरत भी कम हो जाएगी। यह योजना भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी और सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाएगी। स्पष्ट और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त स्वामित्व प्रदान करके यह योजना भूमिधारकों को ऋण लेने और भूमि में निवेश करने के अवसर प्रदान करेगी। इससे न केवल व्यक्तिगत आर्थिक संभावनाओं को बल मिलेगा बल्कि राज्य का समग्र विकास भी होगा।

प्रदेश सरकार की यह पहल प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। जमीन के मालिकाना हक और प्रबंधन की जटिलताओं को संज्ञान में लेकर शुरू की गई स्वामित्व योजना प्रदेश में एक अधिक कुशल, पारदर्शी और भू-प्रशासन प्रणाली की नींव रख रही है। इस योजना से आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा और राज्य की ग्रामीण आबादी के लिए प्रगतिशील आयाम स्थापित होंगे।

ट्राई ने नागरिकों को अपने नाम से धोखाधड़ी करने वाले कॉल के संबंध में आगाह किया

शिमला। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के संज्ञान में यह लाया गया है कि नागरिकों को इस प्राधिकरण से होने का दावा करते हुए बहुत से प्री-रिकॉर्डेड कॉल किए जा रहे हैं। नागरिकों को धमकी दी जाती है कि उनके नंबर जल्द ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनसे कुछ व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए कहा जाता है।

यहां पर यह सूचित किया जाता है कि ट्राई के संदेशों या अन्य माध्यमों से मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने के बारे में ग्राहकों से संचार शुरू नहीं किया जाता है। ट्राई ने ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। इसलिए, ट्राई से होने का दावा करने वाले अथवा मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने की धमकी देने वाले किसी भी प्रकार के संचार कॉल, संदेश या नोटिस को संभावित धोखाधड़ी का प्रयास माना जाना चाहिए और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

बिलिंग, केवाईसी या दुरुपयोग के कारण किसी भी मोबाइल नंबर का डिस्कनेक्ट संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता टीएसपी द्वारा किया जाता है। नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध धोखेबाजों के झांसे में आने से घबराने की सलाह नहीं दी जाती है। उन्हें संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता के अधिकृत कॉल सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करके ऐसी फोन कॉल की पुष्टि करने की भी सलाह दी जाती है।

साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से नागरिकों को दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने के लिए आग्रह किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म को https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर देखा किया जा सकता है। साइबर अपराध के पुष्ट मामलों के लिए, पीड़ितों को निर्दिष्ट साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या आधिकारिक वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ के माध्यम से घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए।

शिमला शहर में चलाया जाएगा 'नो हॉर्न' अभियान:उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक

में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा से संबंधित व वर्ष 2024-25 की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 23.92 करोड़ रुपये की राशि परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों पर व्यय की जा रही है। विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के तहत विभिन्न हितधारक विभागों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के परिणामस्वरूप गत वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 13 प्रतिशत और मृत्यु दर में 14.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

उप-मुख्यमंत्री व परिषद के अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों को सभी हितधारक विभाग तत्परता से पूर्ण करें और इसकी नियमित तौर पर निगरानी और समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेष कर पांवटा साहिब से ऊना में सड़क सुरक्षा संबंधी अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के समीवर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।

यह भी निर्णय लिया गया कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों व योजनाओं पर परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सूचना पट लगाए जाएं। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा समिति के अधिनियम व नियम तैयार करने के लिए जारी आदेशों के बारे में भी अवगत करवाया गया। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा अधिनियम तैयार किए जाएं और आवश्यकतानुसार प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में तैनात विभिन्न हितधारक विभागों के अधिकारी भी सड़क सुरक्षा के अंतर्गत विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं निगरानी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को सशक्त करने के लिए स्टाफ की कमी को दूर करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिमला शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से 'नो हॉर्न' अभियान चलाया जाए व पूरे प्रदेश में भी 'नो हॉर्न' जागरूकता पुस्तिकाएं बांटी जाए। बैठक में परिषद के विभिन्न सदस्यों सहित हितधारक विभागों के विभागाध्यक्षों एवं अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हिमाचल में खदानों की ई-नीलामी करेगा एमएसटीसी:हर्षवर्धन चौहान

राज्य सरकार ने माइनिंग लीज़ के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री सुन्नी तहसील और सोलन जिला की

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है। इस समझौते के तहत प्रदेश में खनन पटे (माइनिंग लीज़) और कम्पोजिट लाइसेंस की ई-ऑक्शन सुविधा उपलब्ध होगी।

निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति और एमएसटीसी के क्षेत्रिय प्रबंधक नितिन आनंद ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला जिला की अर्की तहसील में दो चूना पत्थर खदानों की नीलामी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन खदानों से निकलने वाला चूना पत्थर बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होगा, जिसका सीमेंट, स्टील, शीशा और उर्वरक उद्योगों में उपयोग हो सकेगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि इन खनिज खदानों की नीलामी से जहां प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

प्रधान सचिव उद्योग आर. डी. नज़ीम और राज्य भू-वैज्ञानिक उद्योग विभाग पुनीत गुलेरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हवाई सेवाओं के नए रूट से प्रदेश में पर्यटन को लगेंगे पंख

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार चंडीगढ़-कुल्लू-धर्मशाला को जोड़ने वाले नए हवाई रूट का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के दो प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है जिसके लिए संबंधित एयरलाइंस कंपनी और अन्य एजेंसियों के साथ चर्चा की जा रही है। इसमें कुल्लू और धर्मशाला के बीच नई सीधी हवाई सेवा के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुविधा संपन्न पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नवीन कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में हवाई सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अलौकिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है और यहां पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। प्रदेश सरकार बेहतर पर्यटन अधोसंरचना का विकास कर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित कर रही है जिससे क्षेत्रीय आर्थिकी को बल मिलेगा। प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी।

प्रदेश सरकार के समग्र और समावेशी प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देश के अन्य भागों से हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। लोगों को दिल्ली-शिमला -दिल्ली, शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई सेवा प्रतिदिन और अमृतसर- शिमला-अमृतसर और अमृतसर- कुल्लू-अमृतसर हवाई सेवा सप्ताह में तीन दिन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में हवाई यात्रा सुविधा में वृद्धि करने के साथ-साथ राज्य सरकार नए हेलीपोर्ट भी विकसित कर रही है। प्रदेश की पर्यटन राजधानी जिला कांगड़ा के रक्कड़ व पालमपुर, चम्बा और किन्नौर जिला के रिकांगपियो में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 13 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में हेलीपोर्ट पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी यात्रा सुगम बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में यह हेलीपोर्ट स्थानीय लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करने में मददगार होंगे। इनके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट निर्मित कर रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा को हिमाचल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला में आवश्यक पर्यटन अधोसंरचना को स्तरोन्नत किया जा रहा है। इस दिशा में कांगड़ा हवाई अड का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से यहां बड़े विमान उतर सकेंगे और इससे हवाई यात्र की लागत में भी कमी आएगी। प्रदेश सरकार के इस कदम से क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

आईएसबीटी शिमला में परिवहन चालकों के लिए नेत्र शिविर आयोजित

शिमला/शैल। महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, आईपीएस के निर्देशन में यातायात, पर्यटक और रेलवे टीटीआर विभाग, शिमला द्वारा

आईएसबीटी शिमला में भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के लिए एक दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य परिवहन चालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, जिसमें दीन दयाल उपाध्याय जिला अस्पताल, शिमला की विशेष चिकित्सा टीम ने सहयोग दिया। इस टीम में नेत्र चिकित्सा अधिकारी, ऑप्टोमेट्रिस्ट और तकनीशियन शामिल थे।

शिविर में कुल 105 चालकों के नेत्र परीक्षण किए गए, जिनमें से 7 व्यक्तियों को उन्नत उपचार के लिए नेत्र अस्पताल जाने की सलाह दी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी संभावित नेत्र समस्याओं का समाधान समय पर हो, जिससे सड़क सुरक्षा प्रभावित न हो। विशेष रूप से, प्रतिभागियों में से किसी में भी रंग अंधापन या अन्य नेत्र संबंधी अयोग्यता का मामला नहीं पाया गया। इसके अलावा, 91 व्यक्तियों की एचआईवी, एचसीवी, सिफलिस और एचबीएसएजी के लिए जांच की गई, जिनमें सभी के परिणाम नकारात्मक पाये गये।

इस शिविर के पुलिस समन्वयक, अतिरिक्त एसपी नरवीर सिंह राठौर ने इस प्रकार की पहलों के महत्व पर बल दिया, जो ड्राइवरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक हैं। इस कार्यक्रम को स्थानीय ट्रक, टेम्पो और टैक्सी यूनियनों से भी सराहना मिली, जिन्होंने ड्राइवरों की भलाई के प्रति पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा की।

डीआईजी टीटीआर गुरदेव चंद शर्मा, आईपीएस, ने इस शिविर का दौरा किया और राज्य की सड़क सुरक्षा पहल के तहत इन नेत्र जांच शिविरों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नियमित नेत्र जांच न केवल इष्टतम दृष्टि बनाये रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सुरक्षित ड्राइविंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तरह के शिविर आंखों की समस्याओं की समय पर पहचान, रंग अंधापन से संबंधित दुर्घटनाओं की रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा, यह पहल ड्राइवरों के बीच नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाती है और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करती है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस सुरक्षित सड़कों और स्वस्थ ड्राइवरों को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों को लागू करने के लिए समर्पित है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और मौतों के जोखिम को कम किया जा सके।

जिला कांगड़ा के ढगवार में स्थापित होगा यूनिटी मॉल

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला के निकट गांव ढगवार में निर्मित होने वाले यूनिटी मॉल को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के लिए प्रदेश के राजस्व विभाग ने उद्योग विभाग को 02-67-99 हैक्टेयर की भूमि हस्तांतरित की है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की है और यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

इस योजना के अन्तर्गत यूनिटी मॉल वन स्टॉप बाजार की तरह कार्य करेंगे और राज्य के हथकरघा, जीआई टैग उत्पादों के लिए व्यावसायिक केंद्र की तरह कार्य करेंगे और देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत के विभिन्न राज्यों के उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे।

उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग ने विशेषज्ञों के परामर्श और एचपीएसआईडीसी ने यूनिटी मॉल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और भारत सरकार को अगस्त, 2023 तक यह परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रदेश में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 132 करोड़ रुपये की धन राशि स्वीकृत की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने प्रदेश के योजना विभाग को 66 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है।

उन्होंने कहा कि डीपीआईआईटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार उद्योग विभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) से यूनिटी मॉल के निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया शुरू करेगा।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिटी मॉल में प्रदेश और देश के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पार्किंग, होटल, फूड कोर्ट्स, पीवीआर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी शामिल की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि पीपीटी मोड पर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसके लिए विशेषज्ञों के परामर्श पर सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ उनकी बिक्री के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की और अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी सभी जायज मांगों पर सहानूभतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एरियर जारी करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फायदे में चल रहे सभी बोर्डो और निगमों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए महंगाई भत्ता और एरियर जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करेगी और राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किश्तों पर रोक लगा दी थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है। इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एकसाथ एरियर का भुगतान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं लेकिन यह राशि भी अब तक जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिली हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पैन्शन योजना बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं।

उन्होंने कहा कि ऋण सीमा 6,600 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है। वहीं, अगले वित्त वर्ष के लिए 3500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा, जबकि यह राशि पिछली भाजपा सरकार को प्राप्त राशि से 7,000 करोड़ रुपये कम है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सभी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा और रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी ताकि सभी विभाग सुचारू तरीके से कार्य कर सकें। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का गहरा आभार व्यक्त किया।

कर्मचारी संगठनों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचरियों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का हक दिया।

कर्मचारी संगठनों ने जल्द संयुक्त परामर्श समिति की बैठक करवाने का भी आग्रह किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर, शिक्षक संगठन के अध्यक्ष लोकेंद्र ठाकुर और अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। सद्भावना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला स्थित राजीव चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयन्ती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस शपथ भी दिलाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी को राष्ट्र आधुनिक भारत निर्माता के रूप में जानता है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोगों और समाज की सोच को बदलने के लिए अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वह नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। एनएसयूआई की मांग पर राजीव गांधी ने युवाओं के मताधिकार के उपयोग की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की, ताकि देश का युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उनके कार्यकाल की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी के दूरदर्शी निर्णयों के फलस्वरूप आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब भारत की सुपर कम्प्यूटर की मांग को ठुकराया, तब उनके सशक्त नेतृत्व ने देश ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं के अधिकारों की उन्होंने पुरजोर वकालत की और पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने विधानसभा और संसद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए आवाज उठाई।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा व संजय अवस्थी, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, पार्षदगण, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

गरीब व्यक्ति तक सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जोगिंद्रा सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और बैंक के नए 'लोगो' का अनावरण किया। उन्होंने 7.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बैंक के नए भवन को जनता को समर्पित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये होने पर बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि किसी भी बैंक के कर्मचारी उस संस्था की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक का कुल एनपीए आठ प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत रह गया है। उन्होंने जोगिंद्रा बैंक के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि बैंक का डिपोज़िट 1400 करोड़ रुपये हो गया है लेकिन बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बेहतर काम करने वाली बैंक की शाखाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस वित्त वर्ष में प्रत्येक 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज पर 11 रुपये, कर्ज अदायगी पर नौ रुपये, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपये और बचे हुए 28 रुपये पूंजीगत व्यय और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान भी कम हुआ है। वर्ष 2021-22 में अनुदान के रूप में राज्य सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये मिलते थे जबकि वर्ष 2025-26 में यह अनुदान घट कर तीन हजार करोड़ रुपये रह जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार का विज़न हिमाचल प्रदेश को व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनाना है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, राजनीतिक लाभ के लिए मैं सरकारी खजाने को लुटने नहीं दूंगा। साधन संपन्न लोगों को बिजली और पानी पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तथा सरकार द्वारा इसका युक्तिकरण किया जा रहा है, ताकि गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। सरकार द्वारा उठाए कदमों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। एक वर्ष में अर्थव्यवस्था बीस प्रतिशत सुधरी है। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन भी बेहतर हुआ है।''

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला सोलन के कंडाघाट में प्रदेश के नौ हजार दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के कोटला-बड़ेाग में राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह नशा मुक्ति केंद्र मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता करेगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करेगा।

प्रदेश में दूध की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में मिल्कफेड के माध्यम से दूध की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसका श्रेय किसानों और पशुपालकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए प्रदेश सरकार के निर्णयों को जाता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि दूध की औसत खरीद 1.90 लाख लीटर प्रतिदिन के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है जो पिछले वर्ष की 1.40 लाख लीटर प्रतिदिन की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश सरकार पशुपालन को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल्कफेड द्वारा दूध खरीद के आंकड़ों में स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं।

प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण दुग्ध संग्रहण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दूध में वसा की मात्रा 3.50 प्रतिशत से बढ़कर 3.65 प्रतिशत और सॉलिड-नॉट-फैट की मात्रा 7.50 प्रतिशत से बढ़कर 7.70 हुई है। मिल्कफेड ने गत वर्ष के मई में 11.01 करोड़ रुपये और जून में 11.88 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष मई में 19.42 करोड़ रुपये और जून में 21.42 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। सरकार के यह प्रयास प्रदर्शित करते हैं कि प्रदेश सरकार कृषक समुदाय की आय में बढ़ौतरी के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि गाय के दूध के खरीद मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 55 रुपये प्रति लीटर किया है, जिससे पशुपालकों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के ढगवार में अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसके लिए सरकार ने 201 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस संयंत्र की प्रारम्भिक क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण रूप से स्वचालित इस संयंत्र में दुग्ध आधारित अन्य उत्पाद जैसे दहीं, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, "लेवर्ड मिल्क, खोया और मोज़िला चीज़ जैसे विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद के बेहतर मूल्य मिल सकेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या भाजपा का अघोषित समर्थन है सुक्खू सरकार को?

- अपने ही उठाये मुद्दों पर भाजपा की खामोशी से उठा सवाल
- सीपीएस मुद्दे पर फैसला रिजर्व होने पर भाजपा को याचिकाकर्ता होने के नाते इसे शीघ्र सुनाये जाने की गुहार का हक हासिल है
- सुधीर शर्मा और होशियार सिंह द्वारा उठाये मुद्दों पर भाजपा की खामोशी सवालों में

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने अभी सस्ते राशन के नाम पर मिलने वाले आटे के दाम 2.70 पैसे और चावल 3 रूपये किलो बढ़ा दिये हैं। सीमेंट के दाम दस रूपये बढ़ा दिये हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस कांग्रेस सरकार के शासन में सीमेंट के दाम 70 रूपये प्रति बैग बढ़ाये गये हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि जितना कर्ज उन्होंने पूरे कार्यकाल में लिया था उतना इस सरकार ने पौने दो साल में ही ले लिया है। जिस सरकार को सस्ते राशन के दाम बढ़ाने पड़ जाये उसकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार प्रतिमाह एक हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले रही है। इतना कर्ज लेने के बाद भी सरकार कर्मचारियों, पैन्शनरों के देह भते और संशोधित वेतनमान के एरियर नहीं दे पायी है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं है। बच्चों को अपने आप पढ़ने के लिए कहा गया है। जब तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि टीचर भर्ती करने में डेढ़ वर्ष लगेगा। क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। जब संबंधित विभाग का मंत्री यह कहेगा तो उससे पूरी सरकार की कथनी और करनी का पता चल जाता है। कड़ी मेहनत कर प्रवेश परीक्षा में मैरिट के आधार पर बच्चों को सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिला है और मंत्री यह कहे कि सरकार ने बच्चों को दाखिला लेने के लिये नहीं कहा था तो इससे सरकार की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता और उसकी घोषणाओं का व्यवहारिक सच सामने आ जाता है।

सरकार ने विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाकर पांच हजार करोड़ से अधिक का राजस्व जुटाने का दावा किया है। कर्ज और दाम बढ़ाने के बाद भी जो सरकार कॉलेज में अध्यापकों का प्रबन्ध करने को प्राथमिकता न माने उसके बारे में आम आदमी क्या राय बनायेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। ऐसी वस्तुस्थिति में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर इस पैसे का निवेश हो कहां रहा है? कांग्रेस का हर नेता इस पर चुप है क्योंकि हाईकमान का डर है। विपक्ष सरकार की इस स्थिति पर केवल रस्म अदायगी के लिये ब्यानबाजी कर रहा है। गंभीर मुद्दों पर विपक्ष की चुप्पी सन्देहास्पद है। सरकार ने जब पिछले छः माह के फैसले पलटते हुये सैकड़ो संस्थान बन्द कर दिये थे तब उस पर पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा करने के बाद उच्च न्यायालय में इस संद्धर्भ में याचिका दायर की थी। उसके बाद मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में भाजपा के एक दर्जन नेताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर लम्बे समय से फैसला सुरक्षित चल रहा है। भाजपा नेताओं को याचिकाकर्ता होने के नाते यह हक हासिल है कि यह फैसला शीघ्र सुनाये जाने की अदालत से गुहार लगाये। लेकिन भाजपा चुप है क्यों? यही नहीं विधानसभा उपचुनावों के दौरान सुधीर शर्मा ने नादौन एचआरटीसी द्वारा बनाये जा रहे ई-बस स्टैंड की जमीन खरीद का मामला उठाया था लेकिन अब पूरी भाजपा इस पर चुप है। देहरा में भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के चुनाव शपथ पत्र पर गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर होशियार सिंह और पूरा भाजपा नेतृत्व खामोश है। जबकि इन मामलों की गंभीरता समझने वाले जानते हैं कि इनके उठने से प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जायेगा।

आज जब सरकार को संपन्नता के नाम पर आम आदमी की सुविधाओं में कटौती करनी पड़ रही है तब क्या यह सवाल विपक्ष को नहीं पूछना चाहिये की आखिर पैसे का निवेश हो कहां रहा है? क्या सरकार सही में फिजूल खर्ची कर रही है? जनता के मुद्दों पर विपक्ष की चुप्पी का अर्थ है सरकार को अघोषित समर्थन। यदि भाजपा द्वारा अदालत तक पहुंचाये गये मुद्दे सही में उसकी नजर में अर्थहीन है तो उन्हें तुरन्त प्रभाव से वापस लेकर सरकार को बिना किसी रुकावट के काम करने देना चाहिये। यदि भाजपा अपने में बंटी हुई है तो उसे यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये। यह सही है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व के नाम पर लड़ा था। इसलिये जनता कांग्रेस को सत्ता में लायी थी। आज कांग्रेस का नेतृत्व किस तरह से परफारम कर रहा है उसे झेलना जनता की मजबूरी है लेकिन जनता की इस मजबूरी का स्वभाविक लाभ भाजपा को ही मिलेगा इसे गारंटी नहीं समझा जाना चाहिये। आज इस वित्तीय वर्ष के सात माह शेष बचे हैं अगले दो माह में सरकार की कर्ज लेने की सीमा भी पूरी हो जायेगी। उसके बाद सरकार कैसे चलेगी यह इस समय का गंभीर मुद्दा है। क्या इस मुद्दे पर इस विधानसभा सत्र में चर्चा हो पायेगी इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी रहेगी।

देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रही केन्द्र सरकार:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आहवान पर प्रदेश कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए अडानी व सेबी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उन्होंने अडानी व सेबी प्रमुख के कथित सम्बधों की जांच जेपीसी से करवाने व देश मे जातीय जनगणना करवाने की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने कुछेक पूंजीपतियों को लाभ देने के लिये देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रहीं है। उन्होंने कहा कि सेबी प्रमुख जो कभी अडानी समूह में नौकरी करते थे आज इस समूह को आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचा रहें है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिडंनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी के शेयरों घोटाले के खुलासे में सेबी प्रमुख की संलिप्ता की जांच जेपीसी से करवाई जानी चाहिए क्योंकि इस घोटाले में देश के लाखों शेयर धारकों के करोड़ो रूपये डूब गये। उन्होंने कहा कि सेबी प्रमुख को तुरन्त उनके पद से हटाया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने में जुटे है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जब भी इसके खिलाफ कोई आवाज उठाते है तो उन्हें सीबीआई व ईडी का डर दिखा कर जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश मे वितीय घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह जांच जेपीसी से कम स्वीकार्य नही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज देशभर में इस महाघोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है।

राठौर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिडंनबर्ग के खुलासे के बाद संसद के अंदर इसकी पूरी जांच जेपीसी से करवाने की जो मांग रखी है वह पूरी तरह से सही व जायज है, क्योंकि देश के सामने सच आना चाहिए। किस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा अपने कुछेक खास पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जातीय जनगणना से भी भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश मे जातीय जनगणना की पक्षधर है और इसे करवा कर ही रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की अब कोई भी तानाशाही चलने वाली नही । कांग्रेस इसके खिलाफ मजबूती से लोगों के बीच जाकर आवाज उठाएगी।